विरुद्ध अनेक रिट याचिकाएं, जो उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में लम्बित पड़ी हैं, उन सिफारिशों के कार्यान्वयन न किए जाने के प्रमुख कारण हैं। बछावत वेतन बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। बछावत पंचाट के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार समय समय पर राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों की सरकारों से अनुरोध करती रही है।

Educated persons registered in Employment Exchange in Punjab

748. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) The number of educated/skilled/unskilled persons with their qualifications registered with employment exchange in the country particularly in the State of Punjab;

(b) the details thereof, State-wise/District-wise;

(c) whether Government propose to grant unemployment allowance to the educated persons; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): (a) and (b) State-wise number of educated, skilled/semi-skilled/unskilled job-seekers, all of whom are not necessarily unemployed, on the Live Register of Employment Exchanges is furnished in the Statement annexed. District-wise information is not maintained. [*See Appendix 170 Annexure No. 16]*

(c) and (d) The Central Government is not in favour of paying unemployment allowance to any category of unemployed, including educated unemployed, due to resource constraints. However, as per information available some of the State Governments have been paying such allowance to certain specified categories of job-seekers out of their own resources for a limited period subject to certain specified conditions.

उत्तर प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों और औषधालयों की संख्या

749. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार उनमें से कुछ अस्पतालों/औषधालयों के स्तर का उन्नयन करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) किराए पर लिए गये गैर-सरकारी भवनों में चलाए जा रहे कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों/औषधालयों की संख्या कितनी है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर 16 कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों तथा 131 कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों की स्थापना की गयी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कोई भी कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल किराये के निजी भवन में नहीं चल रहा है। तथापि, 97 कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय किराये के भवनों में कार्य कर रहे हैं।

Legal Protection for Employed Children in the Country

750. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 80% of the employed children have no legal protection in the country;

(b) if so, whether the Child Labour Act provided protection to the children employed in Organised Sector;

(c) whether it is a fact that in India 80% children are in unorganised sector;

(d) if so, whether most of the these 80% children work in Agricultural Sector; and